[श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर]

मैं सिंचाई मन्त्री जी से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निवेदन करता हूं।

(II) FINANCIAL ASSISTANCE FOR RELIEF WORK IN FAMINE—AFFECTED AREAS OF RAJASTHAN, SPECIALLY BARMER AND JAISALMER.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान प्रान्त का पश्चिमी भाग विशेषतः थार रेगिस्तान का भाग बाड़मेर एवं जैसलमेर लगातार चार वर्षों से और प्रान्त का अन्य भाग दो, तीन वर्षों से भयंकर अकाल से पीड़ित है। यह अकाल राज्य का शताब्दी का सबसे बड़ा अकाल है। यह राष्ट्रीय विपदा है।

राज्यों के सीमित साधनों के कारण प्रदेश में और विशेषतः बाड़मेर, जैसलमेर, पाली एवं जोधपुर जिलों में अकाल राहत कार्य बहुत कम संख्या में खोले जाने के कारण लाखों व्यक्ति बेरोजगार हैं। वे भुखमरी की स्थिति में पहुँच गये हैं और वे कई रोगों के भी शिकार हो गये हैं। हजारों पशु मृत्यु के शिकार हो गये हैं। पीने के पानी के संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। राज्य उक्त जिलों में टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई कर रहा है जो प्रति व्यक्ति औसत आधा गैलन भी नहीं मिलता। बिजली के संकट ने अकाल की विभीषिका को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें बिजली के संकट के कारण अपर्याप्त पानी दे रही हैं जिससे ग्रामीणों और उनके मवेशियों को पानी नहीं मिलने से ग्रामीण जनता में घोर असंतोष है।

राज्य में अध्ययन दल ने दौरा किया था और उसने भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर राज्य को सहायता के लिए निर्णय लिया वह भी निराशाजनक है। राज्य ने इस वर्ष सूखे के मुकाबले के लिए 255.13 करोड़ रु० की मांग की थी जिसमें 162 करोड़ रु० राहत कार्यों के लिए मांग की थी जिसमें सिर्फ गैर योजना कार्यों के लिए 3.36 करोड़ और अग्रिम योजना के तहत 36.16 करोड़ रु० की सीलिंग तय की जिसमें राज्य को सिर्फ 23.80 करोड़ रु० मजदूरों को अकाल राहत कार्यों में लगाने के लिये दिए गए जो अकाल की भीषणता को देखते हुए अपर्याप्त हैं।

अतः कृषि मन्त्री से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि वे राजस्थान के विकराल अकाल का मुकाबला करने के लिए विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वित्त मन्त्रालय के पत्र सं० एफ 43 (1) पी० एफ० आई०/79 दि० 25-4-79 पैरा 8 डी के अनुसार तुरन्त से तुरन्त 100 करोड़ रु० अनुदान के तौर पर राज्य को सहायता दे ताकि राज्य की जनता एवं पशुओं को भुखमरी से बचाया जा सके।

2. बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीने का पानी टैंकरों द्वारा पहुँचाये जाने के लिए सेना की सेवाओं को उपयोग में लेने के लिए रक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करें।

3. अकाल राहत क्षेत्रों में पशुओं को बचाने के लिए रेलवे ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहायता के लिए रेलवे मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करें।

(III) IMPLEMENTATION OF PURI COMMITTEES RECOMMENDATION ABOUT PAYSCALES OF NON-INDUSTRIAL WORKERS IN MINISTRY OF DEFENCE.

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : रक्षा मन्त्रालय में कार्य मूल्यांकन करने और

समानता के आधार पर न्यायोचित वेतन-मानों की सिफारिश करने के लिए वर्ष 1974 में न्यायमूर्ति के० सी० पुरी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी थी। समिति ने मई 1979 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। औद्योगिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही समिति की सिफारिशों का आंशिक रूप से क्रियान्वयन किया गया जिन्हें 16-10-81 से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन खेद है कि गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस मामले पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये और उक्त समिति की सभी सिफारिशें तुरन्त लागू की जानी चाहिए।

(IV) SETTING UP OF DIESEL WORKSHOP IN PLACE OF LOCO SHED IN SHORANUR, KERALA.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore) : The loco shed in Shoranur, Karela, was started as far back as 1896. This shed was started with a work force of 25 and today after 86 years of its existence, it has more than 1000 workers working in it. This loco-shed has played an important role in the development of Shoranur.

Now, with the diesalisation of railway engines having been started, this shed is going to be wound up. The result is that about 700 families will have to vacate their quarters and leave the place.

It is said that some of these workers will be absorbed gradually in traffic, signal, electric and other sections. Some, I understand, will be absorbed in the RPF. Also, there is a proposal to construct a parcel container and a workshop for repairing small wagons and some workers will be absorbed there. But even then a large number of workers will not get any job as there is no arrangement to absorb them. This situation has caused great anxiety among the workers and the people of this area in general, as this will cripple the economic life of this area.

In this situation, it is essential to set up a big diesel workshop in place of the loco shed. This alone will ensure the continued development of this area. Therefore, I earnestly request the Government to set up a diesel workshop in Shoranur.

(V) WASTAGE OF COOKING GAS DUE TO NON-AVAILABILITY OF SUFFICIENT LPG SYLINDERS AT BARAUNI REFINERY IN BIHAR.

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पूर्णियां क्षेत्र के बरौनी रिफाइनरी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ, जहां पर इस ईंधन की अत्यल्पता एवं कमी के युग में भी जहां एक ओर जनता को विकराल कठिनाइयों तथा अभाव का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस रिफाइनरी में करोड़ों रुपये की कीमत की खाना बनाने की गैस (एल० पी० जी०) को बरबाद किया जा रहा है तथा उसे यूं ही व्यर्थ में फूंक दिया जा रहा है जिसका कारण आज तक इस ओर सरकार का उचित ध्यान न दिया जाना ही कहा जा सकता है क्योंकि गैस सिलेन्डरों की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिससे यह गैस बेकार में जला दी जाती है। इस महत्वपूर्ण ईंधन का दुरुपयोग हो रहा है और जिसके प्रयोग से जनता को अभी तक दूर रखा गया है। सरकार को तत्काल युद्ध स्तर पर इस ओर ध्यान देकर इस महत्वपूर्ण विषय को सुलझाना चाहिये तथा जनता को लाभान्वित करना चाहिये।